

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 59 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधशासी अभयंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी के माह 11/2016 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14/10/2017 से 31/10/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव ओर अमृत टंडन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25/11/2016 से 06/12/2016 तक श्री वी.एस. पवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2015 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

- (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत प्रतापनगर एवं टिहरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यों का सुधारीकरण व निर्माण कार्य।

- (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	636.49	567.95	1107.98	1107.98	-	-
2015-16	-	-	645.11	607.51	2281.05	2281.05	-	-
2016-17	-	-	676.42	614.63	2070.92	1982.42	-	-
2017-18	-	-	534.21	388.21	6989.69	6858.25	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता

- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तुत जाँच हेतु चयनित कया गया। वधानसभा प्रतापनगर मे मोटना मदननेगी मो.मा. का सुदृढीकरण का वस्तुत वश्लेषण कया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक..... से..... का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/17 तथा 09/17 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 07/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-
- भाग प्रथम - 5743943.00
- भाग द्वितीय - ₹ 287036.00
5. खण्ड के उच्चतम लेखों के अवशेष माह 09/2017 के अन्त में
- | | |
|------------------------------|---------------|
| (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम - | ₹ 8155747.00 |
| (ख) सामग्री क्रय | - |
| (ग) नगद परिशोधन | - |
| (घ) निक्षेप- | ₹ 41016640.00 |
| (ङ) भण्डार- | ₹ 12795040.92 |

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1 : राज्य योजना के अंतर्गत जनपद- टिहरी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में चौड़ीकरण एवं बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य पर ठेकेदार को एल० डी० के रूप में ₹85.85 लाख का अनुचित लाभ, कार्य समाप्ती की निर्धारित तिथि के उपरान्त भी मोबेलाइजेशन अग्रिम ₹39.40 लाख व ब्याज के रूप में उक्त पर देय धनराशि ₹7,63,507.00 की वसूली कया जाना शेष, ठेकेदार के भुगतान देयकों से ₹12,25,084 राया लटी कम वसूली कया जाना तथा कार्य को छोटे छोटे अनुबन्ध अलग अलग समय पर गठन करने से ₹1.75 करोड़ की शासकीय धनराशि की हानि।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद- टिहरी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में चौड़ीकरण एवं बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या: 3730/III(2)/13-05 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 10-06-2013 द्वारा लम्बाई 21.350 कमी. हेतु रू. 1796.91 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य की प्रावधक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.), लो.नि. व., पौड़ी द्वारा पत्रांक: 3928/08(130) याता. (मा.मु.बो.) - पर्व.2013 दिनांक: 20-11-2013 के माध्यम से 21.350 कमी. लम्बाई हेतु लागत ₹1796.91 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य पर चौड़ीकरण एवं बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु कुल 50 अनुबन्ध कए गये थे व आतिथ तक चौड़ीकरण एवं बी.एम.एस.डी.बी.सी. ₹17.97 करोड़ के सापेक्ष ₹8.62 करोड़ व्यय कया गया है।

अधशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी के अभिलेखों की नमूना जांच में आगे पाया गया क बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु खण्ड द्वारा M/s Espan Infrastructure Limited (CB No- 14/SE 8th Circle/15-16 dt 19-12-2015) के साथ कुल लागत ₹13.02 करोड़ का गठित कया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 19/12/2015 व कार्य समाप्ती की निर्धारित तिथि 18/06/2017 थी। आतिथी तक बी.एम.एस.डी.बी.सी. के अपूर्ण कार्य के निष्पादन में कुल ₹3.09 करोड़ का व्यय कया गया है। जब क अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर निम्न वतीय माइल स्टोन निर्धारित कए गए थे।

माइल स्टोन 1	15%	6 माह
माइल स्टोन 2	50%	12 माह
माइल स्टोन 3	100%	18 माह

उपरोक्त तालिका के अनुसार कार्य को 4 महीने वलम्ब होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं कया गया। कार्य पर वतीय व भौतिक प्रगति 24 प्रतिशत (सलग्नक-1 के अनुसार) मात्र है

(10/2017)। इस सम्बंध में खण्ड के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से अनुबन्ध के शर्तों (प्रस्तर संख्या 46) के अनुसार निर्धारित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न किए जाने पर देयकों से देय ₹85.85 लाख (134 दिन X ₹67055 प्रति दिन के हिसाब से) एल० डी० (liquidated damages) की कटौती नहीं की है इस के साथ साथ ठेकेदार द्वारा समय वृद्ध हेतु कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार ठेकेदार को अर्थदण्ड न लगा कर खण्ड द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया साथ ही समय पर निर्माण कार्य पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना यह दर्शाता है कि खण्ड कार्य को सही महत्व नहीं दे रहा है साथ ही ठेकेदार पर नियम अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं कर रहा है जो कि खण्ड की लापरवाही को परिलक्षित करता है। आगे अभिलेखों में पाया गया कि इस कार्य पर:

- अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार Vr.No. 241 दिनांक 19-03-2016 द्वारा ठेकेदार M/s Espan Infrastructure Limited (CB No- 14/SE 8th Circle/15-16 dt 19-12-2015) को ₹. 65 लाख का मोबेलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया था तथा अनुबंध के GCC Clause 48.3 में वसूली के संबंध में प्रावधानित था कि **'The recovery of mobilization advance shall start from bill after the work done exceeds 10 % of the initial contract price or three month from the date of payment of advance whichever period concludes earlier and shall be made at the rate of 15% of the work done in each IPC.'** The recovery of the advance shall be completed when 90% of the work has been completed or prior to the expiry of the *original time for completion whichever is earlier*। अतः clause के अनुसार 03 माह पश्चात ही दिये गये मोबेलाइजेशन अग्रिम की वसूली प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए थी परन्तु खण्ड द्वारा अग्रिम दिये जाने के 11 माह पश्चात (2/2017) से मोबेलाइजेशन अग्रिम की वसूली (Recovery) प्रारम्भ की इस के साथ साथ कार्य समाप्ती की निर्धारित तिथि 18/06/2017 के उपरान्त भी ₹39.40 लाख वसूली किया जाना शेष है। अतः अनुबंध के GCC clause 48.1 (C) में अग्रिम पर ब्याज के संबंध में प्रावधानित के अनुसार (The advance payment shall be repaid with interest @ State Bank of India Prime Lending Rate applicable on the date of release of mobilization advance by deducting from payments otherwise due to the contractor) दिये गये मोबेलाइजेशन अग्रिम की तिथि (Vr. 241 dt 19-03-2016) पर लागू SBI Prime Lending Rate (PLR) @ 10.5% (w.e.f. 18.03.2016) था। इस प्रकार उक्त clause एवं लागू ब्याज दर के अनुसार दिये गये मोबेलाइजेशन अग्रिम की धनराशि ₹65 लाख पर लेखापरीक्षा तिथि तक {11 माह (3/2016 से 2/2017 तक)+ 4 माह (जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017) तक} कुल 15 माह (अक्टूबर/2017 तक) के ब्याज के रूप में देय धनराशि ₹7,63,507.00 (S.I=P*R*T/100 i.e equal to ₹65,00,000.00 × @ 10.50% × 11/200 + ₹65,00,000.00 × @ 10.50% × 4/200) थी, जिसकी वसूली भी लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं की गयी थी।

- Paragraph 21 of UP Financial Hand Book volume-V Part I and paragraph 81 and 82(iii) of उत्तराखंड budget manual lays down that the departmental authority are required to see whether all revenue receipts due to Government are correctly and properly assessed and credited into Government account without undue delay. जब क ठेकेदार के 6 देयकों से अर्जित राया लटी `14,74,421 (9574.16 घन मी० के वरुद्ध मात्र 1619.07 (16.91%) घन मीटर) के वरुद्ध मात्र `2,49,337- काटा गया था जिसके अनुसार उपरोक्त वर्णत बजट/व वतीय नियमो के अनुसार ठेकेदार के भुगतान देयकों से `12,25,084 राया लटी नहीं काटी गयी है।
- अनुबन्ध के clause 13 के शर्तो अनुसार यह भी पाया गया क कार्य पर इन्सोरेन्स भी नहीं करवाया गया है। और खण्ड द्वारा अनुबन्ध के clause 13.3 के अनुसार कारवाही भी सुनिश्चित भी नहीं की थी।
- बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य के अनुबन्ध व आगणन की जांच मे पाया गया क बी.एम.एस.डी.बी.सी. के कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक 10 से 15 प्रतिशत मात्र (सलग्नक 1 के अनुसार) आगणन मे रख कर शासन से ` 2.30 करोड़ के अधिक धन आवंटन की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति प्राप्त की गयी जो वतीय नियमो व बजट मेनुयल के वरुद्ध है।
- प्रा वधक स्वीकृति के अनुसार कार्य पर चौड़ीकरण एवं बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु 2013-14 से आति थ तक कई छोटे छोटे अनुबन्ध कए गये थे जिस कारण से चौड़ीकरण एवं बी.एम./एस.डी.बी.सी मे छोटे छोटे अनुबन्ध अलग अलग समय पर गठन करने से स्वीकृत आगणन के एस० ओ० आर० दर से न कए जाने से `1.75 करोड़ (सलग्नक १ के अनुसार) शासकीय धनराश की हानि हुई जिससे कार्य पर समय से व एक अनुबन्ध कए जाने से बचाया जा सकता था और कार्य को पूर्ण कये जाने हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं पड़ती।

उपरोक्त के सम्बंध मे इंगत कए जाने पर खण्ड ने तथ्यो को स्वीकार करते हुये अवगत कराया क इस संबंध मे कारवाही सुनिश्चित की जायेगी। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः मोटर मार्ग का डेढ लेन में चौड़ीकरण एवं बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य पर ठेकेदार को एल० डी० के रूप मे `85.85 लाख का अनुचत लाभ, कार्य समाप्ती की निर्धारित तिथ के उपरान्त भी मोबेलाइजेशन अग्रम `39.40 लाख व ब्याज के रूप मे उक्त पर देय धनराश `7,63,507.00 की वसूली कया जाना शेष, ठेकेदार के भुगतान देयकों से `12,25,084 राया लटी कम वसूली कया जाना तथा कार्य को छोटे छोटे अनुबन्ध अलग अलग समय पर

गठन करने से 1.75 करोड़ की शासकीय धनराश की हानि का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज़ान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2: बिना IRC-09: 1972 norm के अनुपालन कये मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग लागत `17.97 करोड़ व लम्बगाँव बीजापुर रावत गाँव मोटर मार्ग लागत `14.26 करोड़ का चौड़ीकरण कार्य कया जाना।

Conduct of Traffic census as per IRC-09: 1972 norm

For accurate preparation of preliminary estimate/ detailed estimates of a road work, it is essential that the department has reliable information on traffic density of the existing road, soil strength of the area where the road is being constructed and the status of the existing road in term of the crust thickness.

For assessing the need for widening and strengthening of existing roads, calculation of values of Passenger Car Unit (PCU- Passenger Car Unit-is calculated in terms of load of different vehicles i.e. Motorcycle, Car, Bus, Truck etc. with their corresponding value as 0.5, 1, 3 and 3) and Million Standard Axle (MSA- Million Standard Axle is an indicator of traffic load on a road) based on traffic census data, California Bearing Ratio (CBR) for determining soil strength and Characteristic Deflection (CD) were required for arriving at the crust thickness required as per IRC guidelines.

Records of the division reveal that the division did not conduct any traffic surveys and even could not produce when last traffic survey was conducted by the division. Further, two roads Costing `32.23 करोड़, taken for sample test check in audit namely:

1. मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में चौड़ीकरण एवं बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य लागत `17.97 करोड़ के सापेक्ष कुल व्यय `8.62 करोड़
2. लम्बगाँव बीजापुर रावत गाँव मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं डेढ़ लेने में बागी तक वस्तार कार्य कुल लागत `14.26 करोड़ के सापेक्ष कुल व्यय `9.01 करोड़

were proposed for widening and the detailed estimates were not supported by traffic census reports. However, the competent authorities accorded technical sanction ignoring this basic requirement. It was also noticed that the division did not maintain proper records to monitor the status of existing road. While as per IRC norms the rules provide for conducting traffic census every year for every road and this report of traffic census with Form-3 need to be sent to Zonal Chief Engineers for onward submission to Chief Engineer, Headquarter and Director, Research Institute and the procedure to be followed is that traffic census should be conducted 24 hours a day for seven days, in presence of AEs at least on three days. Nothing in this regard was found at the division level.

उपरोक्त के संबंध में इंगत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क भ वष्य में लेखा परीक्षा द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः **IRC-09: 1972 norm** का अनुपालन न कए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-3: प्राप्त धनराशयो से **deposit** कार्यो पर अधिक व्यय 16.09 लाख कया जाना।

वत्तीय हस्त पस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 580 मे निहित प्रावधानों के अनुसार deposit कार्यो पर व्यय प्राप्त धनराश तक सीमत रखा जाए।

अधशासी अभयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी के निक्षेप मद भाग-III के अभलेखो की नमूना जांच मे पाया गया क खण्ड द्वारा सतम्बर 2017 तक अधीक्षण अभयन्ता 8 वां वृत्त एवं मुख्य अभयन्ता प्रांतीय खंड, नई टिहरी के आकस्मिक व्यय पर ` (-)1608703.00 का अधिक व्यय कया गया। इस संबंध मे खंड के अभलेखो मे यह देखा गया क मुख्य अभयन्ता, टिहरी क्षेत्र, लो.नि. व. नई टिहरी एवं अधीक्षण अभयन्ता, 8 वां वृत्त, लो.नि. व. नई टिहरी को कार्यालय व्यय हेतु इनके अंतर्गत आने वाले खंडो से धनराश प्राप्त कर deposit मद से इस खंड के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं जब क उक्त दोनों कार्यालयो को इस संबंध मे अलग से बजट का प्रावधान बजट मेनुयल के अनुसार होता है।

इस और इंगत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क उक्त हेतु मुख्य अभयन्ता एवं अधीक्षण अभयन्ता द्वारा निर्देशत कया गया था। परंतु खंड इस संबंध मे कोई साक्ष्य उपलब्ध नही करा सका।

अतः खंड द्वारा बजट मेनुयल मे निहित प्रावधानों के वपरीत मुख्य अभयन्ता, टिहरी क्षेत्र, लो.नि. व. नई टिहरी एवं अधीक्षण अभयन्ता, 8 वां वृत्त, लो.नि. व. नई टिहरी के कार्यालय व्यय हेतु इनके अंतर्गत आने वाले अन्य खंडो से धनराश प्राप्त कर deposit मद मे रखते हुए और उस मद से भी ` (-)1608703.00 अधिक व्यय कये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 4:—वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार बिना निर्देश प्राप्त किये अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के निम्नलिखित प्रस्तर संख्या में प्रावधानित था कि :-

प्रस्तर संख्या-524 ठेकेदार से सम्बन्धित लेखों को ठेकेदारों की बही, प्रारूप 43 में पृथक पृष्ठों के संयोग(Set of folios) में लिखा जायेगा जिसमें प्रत्येक ठेकेदार से सम्बन्धित सभी संव्यवहारों के लिए व्यक्तिगत खाता होगा।

प्रस्तर संख्या-524 कार्य सारांश को प्रथमतः उप-प्रखण्ड कार्यालय में तैयार किया जाना चाहिये। इसमें नकदपुस्तिका(Cash book) और सम्बन्धित ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों को दिन प्रतिदिन के हिसाब से लिखना चाहिये तथा अन्तिम प्रभार की वापसी लेखन (write book) और नकदवापसी को ऋणात्मक प्रविष्टि के रूप में लिखना चाहिये। महीने के अन्त में भण्डारण एवं समायोजन संव्यवहारों को सम्मिलित करना चाहिये तथा निर्धारण पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा की उल्लेख किया जाना चाहिये तथा निलम्बित शीर्षक (1) ठेकेदारों को अग्रिमभुगतान (2) ठेकेदारों को प्रतिभूतित अग्रिम और (3) ठेकेदारों के अन्य संव्यवहार के अधीन सकल योग की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए ठेकेदारों के लेखे के बन्दी जमा राशि(Closing Balance) का विवरण दिखाया जाना चाहिये। कार्य सारांश को प्रखण्ड लेखाकार की देखरेख में जांचा और बन्द किया जाएगा जो निम्नलिखित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा—

“इस कार्य सारांश को मेरे देखरेख में मेरे द्वारा जांचा गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी मदों का मिलान ‘ठेकेदारों का विवरण’ ‘ठेकेदारों के सन्दर्भ में बन्दी जमा राशि’ के रजिस्टर से किया है उन्हें सही पाया है।

प्रस्तर संख्या-634 प्रखण्ड से सम्बन्धित सभी निक्षेपण मासिक संव्यवहार के रूप में समेकित अभिलेख के रूप में तैयार किये जाएं तथा उन्हें निक्षेपित कार्य की अनुसूची के प्रारूप 65 में तैयार किया जाएं। प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में दर्शित इस अनुसूची में प्राप्त निक्षेपण की राशि तथा नियत खर्च दोनों माह के दौरान तिथिवार रीति से दिया जाएं।

पूर्ण कार्य के बिना खर्च की गयी राशि की वापसी निक्षेपण की कटौती में ली जाएं, इसलिए ऋणात्मक वसूली के रूप में अनुसूची में इसे प्रदर्शित किया जाये न कि खर्च के रूप में इसे दर्शित किया जाए।

अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट के अभिलेखों की नमूना जांच (06/2017) के दौरान पाया गया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के उक्त प्राविधानों के बावजूद खण्ड के अन्तर्गत टेकेदारो की बही(Contractors Ledger), कार्य सारांश(works abstract) तथा निक्षेपित कार्यों की अनुसूची प्रारूप 65 (Form no. 65 “Schedule of deposit works”) का रखरखाव नहीं किया जा रहा था तथा कार्यालय महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून को मासिक लेखा के साथ संलग्न कर प्रेषित नहीं किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लिखित है कि उक्त का रखरखाव नहीं किये जाने के सन्दर्भ में उच्चाधिकारियों द्वारा ऐसा कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया था इसके बावजूद भी खण्ड द्वारा उक्त अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। आगे यह भी पाया गया कि खण्ड द्वारा सामान्य भविष्य निधि(जी0पी0एफ0) ब्राडशीट का रखरखाव भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था।

उक्त को इंगित किये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि Contractor Ledger की प्रक्रिया की कार्यवाही की जायेगी जब क Work abstract तथा जी0पी0एफ0 ब्राडशीट के रखरखाव में कोई टिपणी अथवा आख्या नहीं दी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि होती है कि उक्त अभिलेखों का रखरखाव खण्ड के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा था, जबकि उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त अभिलेखों का रखरखाव नहीं किये जाने के सन्दर्भ में ऐसा कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये थे

अतः वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार बिना निर्देश प्राप्त किये अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नहीं किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग—दो 'ब'

प्रस्तर 5:- बिना आवश्यकता के मैक्सफाल्ट ड्रम खरीद कर ` 72.35 लाख की धनराश को अवरूद रखा जाना व निर्देशों के वरूध नई दरो पर ठेकेदारो को मैक्सफाल्ट ड्रम निर्गत कर अनावश्यक लाभ पहुंचाना।

खंड के माह 09/2016 के भण्डार लेखे की अर्धवार्षिक लेखाबन्दी के अनुसार कुल `35,06,686.08 का सरप्लस प्रदर्शित हो रहा है। जिस का समायोजन आतिथ तक नहीं किया गया है। तथा खंड के स्टॉक में 1121 मैक्सफाल्ट ड्रम थे तथा रिपोर्ट में निर्देशित किया गया था कि इन्हीं 1121 मैक्सफाल्ट ड्रम को पहले प्रयोग किया जाये। जबकि भंडार पंजिका (Form-8) के अनुसार 09/2016 में 1077 मैक्सफाल्ट ड्रम थे। जिससे 44 मैक्सफाल्ट ड्रम का कुल मूल्य `4,26,800/= का अंतर आ रहा है। आगे भंडार पंजिका की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया मार्च 2016 में खंड के स्टॉक में 1339 मैक्सफाल्ट ड्रम मौजूद थे फिर भी खंड द्वारा फरवरी व मार्च 2016 में 1167 मैक्सफाल्ट ड्रम @6200/= की दर से कुल `72,35,400/= के और खरीदे गये। माह 09/2016 की रिपोर्ट के अनुसार खंड के स्टॉक में 1121 मैक्सफाल्ट ड्रम थे तथा रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हीं 1121 मैक्सफाल्ट ड्रम को पहले प्रयोग किया जाय। इनमें से जून 2017 में 512 मैक्सफाल्ट ड्रम शेष थे फिर भी दिनांक-26.06.2017 को नये खरीदे गए 1167 मैक्सफाल्ट ड्रम में से 48 मैक्सफाल्ट ड्रम जारी किए गए जिससे ठेकेदारो को अनावश्यक ही लाभ पहुंचाया गया।

इस और इंगत किये जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवधि में मैक्सफाल्ट ड्रम की दर काफी कम हो गयी थी एवं खंड को डामरीकरण हेतु भवष्य में मैक्सफाल्ट की आवश्यकता पड़ेगी इस कारण कम दरो का फायदा उठाकर खंड द्वारा अतिरिक्त मैक्सफाल्ट खरीदा गया। तथा कार्य हेतु धनराश कम होने के कारण कम लागत के मैक्सफाल्ट ड्रमो को स्टोर से निर्गत किया गया। खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा कम दर के मैक्सफाल्ट ड्रम निर्गत कर अनावश्यक ही ठेकेदारो को लाभ पहुंचाया साथ ही बिना आवश्यकता के ` 72.35 लाख का मैक्सफाल्ट ड्रम खरीद कर धनराश को अवरूद रखा गया।

अतः बिना आवश्यकता के मैक्सफाल्ट ड्रम खरीद कर ` 72.35 लाख की धनराश को अवरूद रखा जाने व निर्देशों के वरूध नई दरो पर ठेकेदारो को मैक्सफाल्ट ड्रम निर्गत कर अनावश्यक लाभ पहुंचाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर-6: नियमों के वपरीत 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में प्राप्त धनराश का व्ययवर्तन।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/ प्राइवेट संस्थान जैसे जल निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल / पाइप लाइन बिछाने के लिए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य किया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में धनराश संबंधित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है।

अधशासी अभ्यन्ता, प्रांतीय खंड, लो. नि. व., नई टिहरी के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सितम्बर 2016 में 'रोड कटिंग चार्जस' मद से मुख्य अभ्यन्ता नई टिहरी एवं प्रांतीय खंड, लो. नि. व., नई टिहरी के आकस्मिक व्यय हेतु ₹3,46,536.00 खर्च किये गये। डिपॉजिट रजिस्टर 2017-18 के अनुसार अप्रैल 2017 में 'रोड कटिंग चार्जस' के मद ₹4,54,703.00 शेष थे। चूंकि 'रोड कटिंग चार्जस' मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत करने हेतु कटिंग करने वाले वभाग द्वारा लोक निर्माण वभाग को प्रदान की जाती है अतः खंड द्वारा 'रोड कटिंग चार्जस' के मद से आकस्मिक व्यय पर नियम के विरुद्ध किया गया तथा शेष धनराश राजस्व में न डालने के बजाय डिपॉजिट मद में अवरूढ रखा है।

प्रकरण इंगत कर जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि त्रुटिवंश उक्त देयकों का भारण रोड कटिंग चार्ज पर कर किया गया था जिसे अंतरण प्रवृष्टि से ठीक कर लिया जाएगा। खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में धनराश संबंधित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है और अवशेष पड़ी धनराश को राजस्व में जमा नहीं किया गया है।

अतः खंड द्वारा नियमों के वपरीत 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में प्राप्त धनराश से मुख्य अभ्यन्ता नई टिहरी एवं खंड के आकस्मिक व्यय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1: नव निर्माण/ पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण के स्वीकृत कार्यों पर प्रमुख अभ्यन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किया जाना।

Particular attention needs to be paid to environment while taking up new road construction projects. Extensive plantation alongside the roads is desired.

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखण्ड के मार्गों पर प्लांटेशन का कार्य किया जाये जिस के लिए प्रमुख अभ्यन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा खंडों से अनुरोध किया गया था उनके क्षेत्र के मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर प्रस्ताव भेजे (02/2014)। इस के अतिरिक्त प्रमुख अभ्यन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा नव निर्माण/ पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण के कार्यों हेतु रोड साइड plantation हेतु मानक के अनुसार 1.20 लाख / कमी० की दर 12-05-2015 से आगणन में गठित किए जाने हेतु निर्धारित किए थे। लेकिन खण्ड में उपलब्ध वर्ष 2015-16 व 2016-17 के आगणन में यह पाया गया कि खण्ड द्वारा आगणन में कोई प्रावधान रोड साइड plantation के लिए नहीं रखा गया जबकि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार खण्ड द्वारा नव निर्माण के मार्गों के 171 कार्यों में कुल 289.26 कमी० में 1.20 लाख / कमी० की दर से 347.11 लाख का प्रावधान आगणन में न रख कर प्रमुख अभ्यन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

इस और इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया कि भविष्य में आगणनों में Plantation हेतु धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः नव निर्माण/ पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण के स्वीकृत कार्यों पर प्रमुख अभ्यन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्जान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2: रमसा के अंतर्गत नव निर्मित भवन पर ` 32.45 लाख के व्यय के उपरान्त उद्देश्यो के अनुरूप निर्माण व उपयोग सुनिश्चित न कए जाने से छात्र छात्राओ को निर्मित भवनो की सुवधा से वंचित।

खण्ड के अभिलेखो व पत्रवाली के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जाखनीधार विकासखण्ड मे राजकीय इंटर कॉलेज कपरियासेन मे ` 36.85 लाख के लागत से कम्प्युटर, वज्ञान, लाइब्ररी, कला कक्ष व शोचलाय के निर्माण कार्यो के लए जिला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टिहरी (सभी के लए माध्यमिक शिक्षा परिषद) ने अधशासी अभ्यन्ता, प्रा०खा०, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी के साथ (9/2015) मे एमओयू (अनुबन्ध) कया था।

उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार:

- एमओयू पत्र मे हर निर्माण कार्य हेतु समय सारणी निर्धारित की गयी थी।
- एमओयू पत्र के बिन्दु संख्या 19 मे उल्लिखित शर्तो के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराश के अंतर्गत तथा स्वीकृति आगणन के अनुसार ही पूर्ण करना था।
- खण्ड को जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टिहरी द्वारा अवगत (10/2015) कराया गया था क सम्झौता ज्ञापन मे उल्लिखित समस्त इकाइयो का निर्माण स्वीकृत धनराश मे ही करना है। निर्माण इकाइयो मे कोई भी परिवर्तन राज्य परियोजना कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड देहरादून की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना अनुमान्य नहीं है। इस के अतिरिक्त अभिलेखो के अनुसार मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा 13/4/2016 को यह निर्णय लया गया था क लोक निर्माण वभाग द्वारा ऐसे निर्माण कार्य जो कार्य की मात्रा कम कर प्रारम्भ कये गये है उन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्ण मात्रा के रूप मे, पूर्ण करवाया जाये व इस हेतु व्यय होने वाली अतिरिक्त धनराश को राज्य सरकार द्वारा वहन कया जायेगा।

उपरोक्त के सम्बंध मे खण्ड के लेखा अभिलेखो व पत्रवाली की जांच मे पाया गया जाखनीधार विकासखण्ड मे राजकीय इंटर कॉलेज कपरियासेन मे कम्प्युटर, वज्ञान, लाइब्ररी, कला कक्ष के लए अनुबन्ध 150/EE दिनांक 10/2015 कुल ` 32.45 लाख का ही कया गया था जिसमे शोचलाय का निर्माण एमओयू पत्र के बिन्दु संख्या 19 मे उल्लिखित शर्तो व जिला

परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यामिक शिक्षा अभियान टिहरी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था इस के विपरित खण्ड द्वारा निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन ₹43.79 लाख को शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निदेशक राष्ट्रीय माध्यामिक शिक्षा देहरादून प्रेषित किया गया था (12/2015) जिसकी आतिथ (10/2017) तक राज्य सरकार से कोई अनमोदन प्राप्त नहीं हुआ है (उपलब्ध पत्रवाली के अनुसार)। अनुबन्ध के अनुसार कार्य 1/10/2015 पर आरम्भ व 30/9/2016 पर पूर्ण किया जाना था। इस संदर्भ में अभिलेखों में पाया गया कि राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत दिसम्बर 2016 तक पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पर निर्माण रोक गये हैं। अतिथ तक उपरोक्त निर्माण कार्यों पर खण्ड द्वारा प्राप्त धनराशि ₹18.42 लाख के विरुद्ध ₹27.43 लाख (₹25.85 लाख सबल कार्य पर + ₹1.57 लाख electrification हेतु) माह 9/2017 का भुगतान किया जा चुका है व ₹5.17 लाख ठेकेदार से प्राप्त देयक का भुगतान होना शेष है। यह भी पाया गया कि खंड द्वारा प्राप्त धनराशि से अधिक भुगतान (₹9.01 लाख) अन्य कार्यों से व्यय वर्तन करते हुए किया गया है जो वृत्तीय नियमों के विरुद्ध है।

इस और इंगित कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदार के प्रार्थना पर भुगतान किया गया है व इस का समायोजन धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा तथा पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त ही शौचालय व समस्त शेष कार्य पूर्ण किया जायेगे। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः खंड द्वारा ठोस कारवाही न कए जाने व क्लाइंट वभाग से तालमेल न रखे जाने के कारण नव निर्मित भवन का उद्देश्यों के अनुरूप निर्माण व उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण छात्र छात्राओं को निर्मित भवनों की सुविधा से वंचित रखे जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 3: उप खनिजो पर `32.64 लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 तथा संख्या-842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अधिसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लिखित उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्थापित /संशोधित किया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लिखित था कि यह अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अधिसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक-26.02.2016 से 18.05.2016 तक `194.50, दिनांक-19.05.2016 से 27.10.2016 तक `154.00 प्रति घन मीटर संशोधित /वृद्ध किया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधशासी अभयंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी कार्यालय के संबंधित अभिलेखों, माप पुस्तिकाएँ एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जाँच में पाया कि उक्त लिखित अधिसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती 1 मार्च 2016 से मई 2016 तक नहीं की गई थी।

खण्ड के द्वारा 1 मार्च, 2016 से मई 2016 तक कुल ` 28.11 लाख कटौती कर जमा किया गया था जबकि संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो ` 60.75 लाख रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त होती अर्थात् ($\text{` 60.75 लाख} - \text{` 21.11 लाख} = \text{` 32.64 लाख}$) ` 32.64 लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

उक्त को इंगत करने पर खण्ड ने उत्तर में उल्लिखित किया कि उक्त अवधि में खंड द्वारा जो भी भुगतान किया गया वह उपरोक्त अवधि से पूर्व के देयकों से संबन्धित थे। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि देयकों के भुगतान की तिथि को, जो भी रायल्टी की दर होती है, उसी दर से रायल्टी की कटौती की जाती है। अतः संशोधित दरों से ही रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी। अतः ` 32.64 लाख रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 4: **Retroactive Financing** के तहत कराये गये कार्यों पर प्रकीर्ण अग्रम मद मे असमायोजित धनराश 46.51 लाख।

खण्ड के अभलेखो की जांच व पत्रवाली के अनुसार वर्ष 2013-14 के अंतर्गत देवीय आपदा माह जून 2013 से अक्टूबर 2013 तक व भन्न मोटर मार्गो को यातायात खोलने हेतु खण्ड द्वारा 95.98 लाख का व्यय कया गया था जो खण्ड के अनुसार वश्व बैंक द्वारा **Retroactive Financing** के तहत (reimbursement) अदा कया जाना प्रस्तावत था। लेकन खण्ड को इस संदर्भ मे **Retroactive Financing** के तहत कोई धनराश आतिथ तक प्राप्त नहीं हुई है जिस कारण से खण्ड द्वारा इस राश को प्रकीर्ण अग्रम मद मे रखा है। आगे अभलेखो मे यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा देवीय आपदा मद मे प्राप्त वभागीय आवंटन 15.30 लाख व 8.52 लाख का समायोजन प्रकीर्ण अग्रम मद मे रखे 95.98 लाख मे कया इस के उपरांत खण्ड द्वारा वतीय नियमो/बजट मेनुयल एवं सुसंगत लेखांकन के वरुध प्राप्त वार्षक अनुरक्षण मद के आवंटन से 25.13 लाख (19.88 लाख 2014-15 मे आवंटन + 5.25 लाख 2015-16 मे आवंटन) का समायोजन प्रकीर्ण अग्रम मद के शेष रखे 71.63 लाख मे कया तथा आतिथ पर प्रकीर्ण अग्रम मद मे 46.51 लाख समायोजन हेतु (10/2017) शेष है।

जब क प्रमुख अभयंता द्वारा साफ दिशा निर्देश दिये गये थे क इस प्रकीर्ण अग्रम का समायोजन जिला अधकारी से इस वषय मे धन आवंटन प्राप्त कर के कया जाए अथवा व भन्न योजनाओ मे उपलब्ध बचत यथा **contingency** मद से वतीय नियमो/बजट मेनुयल एवं सुसंगत लेखांकन के अनुसार कया जाये। जब क खण्ड द्वारा जिला अधकारी से इस वषय मे धन आवंटन प्राप्ति कये जाने हेतु कोई कारवाही नहीं की गयी है। अतः खण्ड द्वारा प्रमुख अभयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं कया।

इस और इंगत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क उपरोक्त भुगतान के संबंध मे प्रमुख अभयंता द्वारा आदेश दिया गया है क उक्त मद का समायोजन अन्य कार्यों के बचत से कया जाए। उत्तर तर्क संगत नहीं है कयो क खंड द्वारा जिला अधकारी से इस वषय मे धन आवंटन प्राप्त कये जाने हेतु कोई प्रयास नहीं कया है साथ मे खंड मे कसी भी कार्य पर बचत नहीं हो रही है अगर होगी भी उक्त का समायोजन अन्य कार्यों के बचत से कया जाना वतीय नियमो/बजट मेनुयल एवं सुसंगत लेखांकन के वरुध है।

प्रकरण उच्च अधकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 5: निरीक्षण के सम्बंध मे शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन ।

शासन द्वारा लोक निर्माण वभाग के अ धकारियों के लये निर्माणधीन मार्गो/सेतुओ के निरीक्षण हेतु निम्न समय सारणी (जुलाई 2014) दी गयी थी।

1. अ धशासी अ भयन्ता:

✓ ` 1 करोड से अ धक लागत के समस्त कार्य प्रेत्यक दो माह मे

2. सहायक अ भयन्ता

✓ अपने क्षेत्र से संबन्धित समस्त कार्य प्रेत्यक माह मे

तथा मार्गो का निरीक्षण कर अपनी जांच आख्या प्रमुख अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग के माध्यम से शासन को प्रेषत कया जाना था।

खण्ड के फार्म 64 (9/2010) मे `1 करोड से अ धक लागत के 132 कार्य लागत ` 326.09 करोड जिन पर आति थ तक ` 61.53 करोड व्यय कया जा चुका है को प्रेत्यक दो माह मे निरीक्षण कया जाना था ले कन वगत दो वर्ष 2015-16 व 2016-17 से मार्गो का निरीक्षण कर कोई जांच आख्या प्रमुख अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग के माध्यम से शासन को प्रेषत नहीं कया गया था (प्रस्तुत निरीक्षण पत्रावली के अनुसार)। निरीक्षण पत्रावली के अनुसार यह भी पता नहीं चला पाया की कुल कतने निरीक्षण वगत 2 वर्षो मे इन 132 कार्यो पर शासना देश के अनुसार कए गए है।

आगे यह भी पाया गया क सहायक अ भयन्ता द्वारा भी अपने क्षेत्र से संबन्धित समस्त कार्य जिनका प्रेत्यक माह मे निरीक्षण कया जाना था के जांच आख्या संबन्धित उच्च अ धकारियों को प्रेषत नहीं की है जो शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।

उपरोक्त के संबंध मे इंगत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क भ वष्य मे लेखा परीक्षा द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः निरीक्षण के सम्बंध मे शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

प्रस्तर 6: प्राकलन स्वीकृति से 5 वर्षों से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के बाद 35 कार्यो कुल लागत 20.99 करोड़ वतीय हस्त पुस्तिका 6 के प्रस्तर संख्या 380 के अनुसार खण्ड द्वारा स्वीकृति निरस्त न करना अथवा कार्य प्रारम्भ न कया जाना।

वतीय हस्त पुस्तिका 6 के प्रस्तर संख्या 380 के अनुसार The approval or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded.

खण्ड के अभिलेखो मे पाया गया क ऑडिट आपत्त 2012-13 के आधार पर खण्ड द्वारा 17 कार्यो (संलग्नक-2 के अनुसार) को शासन से निरस्त कए जाने हेतु लखा (02/2014) जिस की संस्तुति शासन से अप्राप्त है। आगे अभिलेखों की कार्य निष्पादन प्रगति समीक्षा में देखा गया क सम्प्रेक्षा अवधि (10/2017) पर 5 से 12 वर्ष पूर्व के 11 स्वीकृत कार्य या तो प्रारम्भ ही नहीं कये गये अथवा टोकन व्यय भारित कर उनके सापेक्ष प्रगति नगण्य है। संलग्नक-1 के ववरण के अनुसार इन 11 कार्यो के स्वीकृत लागत 879.98 लाख के सापेक्ष कुल `15.04 व्यय (1.71%)) है। इस के अतिरिक्त अभिलेखो में यह भी देखा गया क संलग्नक-1 में दर्शाये गये वर्ष 2014-15 के 24 कार्यो पर प्रारम्भ के पश्चात पर्याप्त समयान्तराल (4 से 5 साल) बाद भी प्रगति काफी धीमी थी और आतिथ तक उक्त 24 स्वीकृत कार्यो की लागत `1209 लाख के सापेक्ष कुल व्यय `8.87 लाख (0.73%) है। खण्ड के अभिलेखो के अनुसार कार्यो के सापेक्ष वांछित स्वीकृति के पश्चात भी व पर्याप्त समयान्तराल बाद भी कार्यो का निष्पादन न होना अथवा नगण्य प्रगति होने का मुख्य कारण समरेखण ववाद,ग्रामीण ववाद है जो या तो खण्ड शकलता के कारण वगत 4 से 12 वर्षों से सुलझा नहीं पाया है अथवा खण्ड अब इन मार्ग निर्माण कार्यो को नहीं करना चाहता है। इस के साथ साथ वर्तमान एसओओआरओ की दर के अनुसार अब इन कार्यो को उक्त स्वीकृत धनराश से भी पूर्ण भी नहीं कया जा सकता है।

उपरोक्त के संबंध मे इंगत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क हस्तान्तरण न होने, वनभूम एवं समरेखण निर्धारण मे आम सहमति न बनने के कारण कार्य बाधत हैं। सभी कार्यो को यथा समय पूर्ण करने हेतु प्रयास कए जा रहे हैं। खण्ड से सम्प्रेक्षा में उठाये गये प्रकरण पर वतीय हस्त पुस्तिका 6 के प्रस्तर संख्या 380 के अनुसार कृत कार्यवाही अपेक्षत रहेगी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 7: `1.12 करोड़ की प्रतिभूति धनराश (Security Deposit) की प्रत्याहरण(Refund) की देयता।

जुलाई 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनराश कोषागार में जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती थी। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारों के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन किया गया। ऑन लाइन भुगतान में ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनराश भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार में जमा हो रही हैं।

खंड की मासिक लेखा जून 2014 की जांच में पाया गया है कि Form-79-Schedule of Deposit (Part-II) के अनुसार `1,11,49,477.00(एक करोड़ ग्यारह लाख उनचास हजार चार सौ सत्तर रुपये मात्र) ठेकेदारों के प्रतिभूति धनराश का भुगतान किया जाना शेष है और खण्ड के पास उक्त धनराश के प्रत्याहरण हेतु कोई डीसीएल उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाता है कि खण्ड द्वारा इस धनराश को अन्य कार्यों पर पूर्व में व्यय किया गया है। जबकि उक्त धनराश को खण्ड द्वारा उचित लेखा शीर्षक के बचत मद में रख कर नियमानुसार ठेकेदारों को भुगतान किया जाना था। ऐसा न करने के कारण खंड द्वारा अधीक्षण अभियंता 8 वां वृत्त लो.नि. व. नई टिहरी को दिनांक-19.08.2015 के लखे गए पत्र में ठेकेदारों को प्रतिभूति धनराश की प्रत्याहरण (Refund) हेतु बजट आवंटन की मांग भी की है जो नियम के वरुद्ध है।

इस और इंगत किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख अभियंता द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सी.सी.एल. बचत से उक्त प्रतिभूति का भुगतान किया जाये। जो कि नियम के वरुद्ध है और वगत कई वर्षों से खण्ड के सी.सी.एल. मद में कोई बचत नहीं हो रही है।

अतः जुलाई 2014 से पूर्व ठेकेदारों से प्राप्त प्रतिभूति धनराश `1,11,49,477.00(एक करोड़ ग्यारह लाख उनचास हजार चार सौ सत्तर रुपये मात्र) का प्रत्याहरण (Refund) नहीं किये जाने एवं भविष्य में सी.सी.एल. बचत से भुगतान करने की संभावना का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का ववरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	30/89-90	1,2,3	-	
2	16/90-91	1	4,5	
3	72/93-94	-	1,2	
4	186/95-96	-	1	
5	151/96-97	-	2	
6	163/97-98	1,2	-	
7	225/98-99	-	3	
8	129/99-2000	2	3	
9	36/2001-02	1,2	-	
10	10/2002-03	3	4	
11	98/04-05	-	4	
12	13/2007-08	1,2	2,3,4	
13	57/08-09	-	2	
14	81/10-11	1,2	-	
15	90/11-12	-	2,3	
16	73/12-13	-	1,2	
17	86/2015-16	-	1,2	
18	100/2016-17	-	1,2,3,4	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनिस्तारित प्रस्तरो का उत्तर उच्चा धकारियों को प्रेषत कये गये थे, निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी अवगत कराया गया।	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य
शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभयंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएं:

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
----------	-----	-------

(i)	श्री कलम सिंह नेगी	अधशासी अभयंता 02.07.2016 से अब तक
-----	--------------------	-----------------------------------

(ii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1.	श्री आर. बी. एस. राणा	29.06.2015 से अब तक
----	-----------------------	---------------------

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थक खण्ड-II